राग दरबारी

जांच, जांच और जांच जारी है ज़नाब!

सर, ये दूषित पानी से होने वाली मौत पर तो आपके निर्देशानुसार जांच के आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं। लेकिन हाल ही की कफ सीरप से हुई मौतों की जांच रपट अभी आई नहीं है। उसके बारे में लोग सवाल उठाएं तो हमें क्या कहना है?

आप कब से इस पद पर हैं!आपको यह भी नहीं पता कि पिछली घटनाओं और उसकी जांच पर पब्लिक कभी सवाल नहीं उठाती।या तो विपक्षी दल उठाते हैं या फिर गोद से उतर चुका मीडिया।अभी विपक्ष के लिए तो करंट घटना मुख्य मुद्दा बना हुआ है, इसलिए पिछली घटना वे विस्मृत कर चुके हैं। जहां तक मीडिया का सवाल है,हम उसे गोद में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं।

सर आप महान हैं। आपके निर्देशानुसार ही बिना परमिट चल रही बस के भीषण रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में भी हमने जांच के आदेश प्रसारित कर दिए थे।साथ ही बिना परमिट चल रही बसों की जांच करने के निर्देश भी सम्बन्धित विभाग को देकर जन विश्वास जीतने का प्रयास कर लिया है।÷मातहत ने यह सब ऐसे पढ़ा, जैसे मृतकों की सूची नहीं, विभाग की उपलब्धियां गिना रहा हो। हर वाक्य के बाद उसके चेहरे पर संतोष था,क्योंकि कहीं भी दोषी शब्द नहीं आया था। केवल जांच थी। व्यवस्था का सबसे सुरक्षित शब्द।

साहब ने गंभीरता से सिर हिलाया,धीमे स्वर में बुदबुदाए,÷क्या करें अपनी मजबूरी है।अपनी ही पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं,लाख समझाने के बाद भी परमिट नहीं लेते! ठेकों में पर्सेंटेज भी बहुत बड़ा रखा है! बहरहाल, रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ मामले में क्या हुआ?

सर, रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ मामले में भी जांच रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए रिमाइंडर कर दिया है। और हां सर, पिछले साल अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की भी जांच पूरी नहीं हुई थी,हाल ही की घटना के बाद उस फ़ाइल को भी खोजकर जांच अधिकारी को जांच प्रतिवेदन हेतु अंतिम अवसर दे दिया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा।

अब बॉस के ठहाका लगाने की बारी थी, बमुश्किल ज़ब्त करते हुए बोल पड़े, अंतिम अवसर!कितनी फाइलों में, कितनी बार, कितनों को अंतिम अवसर हम दे चुके हैं।

सर,आप कृपावंत हैं, कृपा निधान हैं। जांचकर्ताओं पर तरस खाकर आप कितनी ही बार अंतिम अवसर दे चुके हैं। आपकी बलिहारी है। अपनी रीढ़ खोजते हुए वह नतमस्तक हो गया और अपने असिस्टेंट के मार्फ़त बुलवाई गई फाइलों के पुलिंदे को मेज पर रखवाकर राहत की सांस लेने लगा,जैसे उसने नहीं, बल्कि जांचों ने अपना काम पूरा कर लिया हो।

इस वार्तालाप के बाद साहब बहादुर ने गंभीर मुद्रा बना ली। गंभीरता उनके चेहरे पर नहीं, उनके कुर्सी के हत्थों में ज्यादा झलक रही थी। ठीक है, उन्होंने कहा, सब पर नजर रखिए। जांच सबसे ज्यादा जरूरी है।

यह सुनकर मातहत का आत्मविश्वास और बढ़ गया। आखिर शासन-प्रशासन में मौत नहीं, जांच सबसे पवित्र प्रक्रिया है। मौतें तो आती-जाती रहती हैं, लेकिन जांच जांच चलती रहनी चाहिए।दूषित पानी से लोग मर गए, जहां मर गए वहां कारणों की खोज,और जहां पानी पहुंचा पा रहे या नहीं पहुंचा पा रहे, वहां पानी के दूषित होने की खोज यानी जांच। कफ सीरप से बच्चे चले गए,कफ सीरप की गुणवत्ता से लेकर पिलाने वाले तक की जांच! और फिर चहुंओर कफ सीरप बनाने और उसके उपयोग की जांच।

स्वयंभूओं की चरण रज पाने की आपाधापी में भगदड़ में कुचल कर भगवान को प्यारे हो गए या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की मारामारी में नारकीय यात्रा के साथ स्वर्ग लोक का टिकट कटवाते लोग, कारणों की खोज, उत्तरदायित्व का निर्धारण करने के लिए जांच। अवैध पटाखा फैक्ट्री फट गई, त्रुटि कर्ता खोजने से लेकर कहां -कहां अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चल रही है, दोषी कौन,जांच जारी है। लगता है कि अगर कभी जांच से किसी की जान चली जाए, तो संभव है उसकी भी जांच बैठा दी जाए।

जांच का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह समय खरीदती है। इतना समय कि जनता थक जाए, मीडिया ऊब जाए और फाइलें स्वयं रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाएं। जांच रिपोर्ट वही दस्तावेज़ है, जो 'शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी' कहते-कहते इतिहास बन जाती है।

साहब बहादुर ने फाइलों के ढेर में से एक फाइल खोली। इसमें क्या है?

सर, यह जांच आयोग की रिपोर्ट है।यह सदन में प्रस्तुत की जा चुकी है।कुछ मरियल से अधिकारियों की बली ली जा चुकी है।

तो फिर इसे सील करके रख दीजिए। अब इसकी क्या जरूरत है।

सर ,यह रिफरेंस के लिए रखी हुई है।जांच रिपोर्ट का यही सौंदर्य शास्त्र है।वह निष्कर्ष नहीं देती, केवल संदर्भ देती है।उसमें 'प्रथम दृष्टया', 'संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता', और 'उत्तरदायित्व तय किया जाना शेष है' जैसे अमर वाक्य होते हैं। दोषी इतने धुंधले रहते हैं कि पहचान पत्र भी बनवाने लायक नहीं होते।÷यह कहकर मातहत मन ही मन सोच रहा था कि कभी-कभी किसी जांच में कोई छोटा कर्मचारी फंस जाए, तो व्यवस्था तक दुखी हो जाती है। और कह बैठती है नहीं-नहीं, यह बड़ी साजिश है। इसकी भी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।

इस तरह एक जांच, दूसरी जांच को जन्म देती है। जांच का वंशवृक्ष फैलता रहता है,जैसे पीढ़ियों से केवल जांच ही पैदा हो रही हो।इस देश में कुछ भी स्थायी नहीं है,सिवाय जांच के। जांच ज़िंदा है! नजर सिर्फ जांच पर रहनी चाहिए। बाकी सब तो हादसे हैं–ईश्वर की इच्छा, तकनीकी कारण, मानवीय भूल, या फिर दुर्भाग्य।इस देश में आदमी मरता है तो शोक नहीं होता, जांच बैठती है।जांच बैठती है तो व्यवस्था खड़ी हो जाती है।

जांच रिपोर्ट वही दस्तावेज़ है, जिसे पैदा होते ही भविष्यकाल में भेज दिया जाता है। वह कभी आएगी, कभी आ रही है, कभी अंतिम चरण में है,और एक दिन अचानक प्रासंगिक नहीं रहती।अगर बहुत दबाव पड़ जाए तो यह घोषणा हो जाती है कि ÷उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं।÷यह वाक्य लोकतंत्र का ब्रह्मास्त्र है। इसके बाद न तो सवाल बचते हैं, न जवाब की गुंजाइश। मीडिया शांत, जनता व्यस्त और दोषी सुरक्षित।इस देश में अगर कुछ सुरक्षित है, तो वह आदमी नहीं,जांच है।

डॉ प्रदीप उपाध्याय

महाराष्ट्र निकाय चुनाव 2026: सत्ता, संगठन और संघर्ष का नया गणित

गंतव्य से आगे

प्रमुख जीत के क्षेत्र:

- मुंबई के 15 में से 9 विधानसभा क्षेत्रों में बहुमत
- कोंकण क्षेत्र की 23 नगरपालिकाओं में से 17 में बहुमत
- मराठवाड़ा के शहरी केंद्रों में मजबूत उपस्थिति

अब शिंदे गुट केवल सरकार में भागीदार नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की स्थायी सत्ता-धुरी बनने की ओर बढ़ चुका है।

उद्धव ठाकरे: विरासत बचाने की कठिन जंग

दूसरी ओर, उद्धव ठाकरे गुट ने मराठी अस्मिता और भावनात्मक अपील के सहारे मैदान में संघर्ष किया। लेकिन निकाय नतीजों ने दिखाया कि भावनात्मक राजनीति अब संसाधन-संगठित राजनीति के सामने कमजोर पड़ रही है।

ठाकरे गुट का प्रदर्शन:

- कुल सीटें जीतीं-1,284 (सभी निकायों में)
- जीत प्रतिशत: 37.8%
- BMC में: 38 सीटें (2017 में 84 से भारी गिरावट)
- मुंबई में वोट शेयर: 23.4% (2017 में 40.8% से कम)

संघर्ष के क्षेत्र:

BMC से बाहर होना ठाकरे परिवार की राजनीतिक प्रतिष्ठा को सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि कुछ पुराने गढ़ों में उन्होंने पकड़ बरकरार रखी:

- मातोश्री के आसपास के 4 वार्डों में जीत
- पालघर जिले की 7 नगरपालिकाओं में बढ़त
- रायगढ़ जिले के कुछ तटीय क्षेत्रों में मजबूती

लेकिन समग्र रूप से वे अब सत्ता नहीं, बल्कि संघर्ष की राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। बाला साहेब ठाकरे स्मारक मातोश्री सहित भावनात्मक मुद्दों के बावजूद जमीनी हार ने साबित किया कि केवल विरासत पर्याप्त नहीं है।

भाजपा- शहरी विस्तार की सफलता

भाजपा ने इस चुनाव में अपनी शहरी पकड़ को और मजबूत किया:

भाजपा का प्रदर्शन:

- कुल सीटें जीतीं: 2,956 (सभी निकायों में)
- जीत प्रतिशत: 62.7%
- BMC में: 52 सीटें (सबसे बड़ी पार्टी)
- विदर्भ क्षेत्र: 78.4% सीटें
- मराठवाड़ा: 58.9% सीटें
- उत्तर महाराष्ट्र: 64.3% सीटें

प्रमुख उपलब्धियां:

- नागपुर में पूर्ण बहुमत
- औरंगाबाद, नांदेड़, अमरावती में स्पष्ट बढ़त
- पश्चिम महाराष्ट्र के शहरी केंद्रों में विस्तार

शरद पवार गुट: संघर्ष और आशा

एनसीपी विभाजन के बाद शरद पवार गुट के लिए यह चुनाव राजनीतिक अस्तित्व की परीक्षा था।

शरद पवार एनसीपी का प्रदर्शन:

- कुल सीटें जीतीं: 892 (सभी निकायों में)
- जीत प्रतिशत: 41.2%
- पश्चिम महाराष्ट्र: 567 सीटें (मजबूत आधार)
- सातारा, सांगली, कोल्हापुर: 68% सीटें

मजबूत क्षेत्र:

- बारामती तालुका: 89% सीटें
- इंदापुर क्षेत्र: 76% सीटें
- सहकारी क्षेत्र प्रभावित शहर- मजबूत उपस्थिति

लेकिन शहरी निकायों में समग्र रूप से सीमित प्रभाव ने यह संकेत दे दिया कि नई पीढ़ी और संसाधन-आधारित राजनीति में संगठन विस्तार बड़ी चुनौती है।

अजित पवार एनसीपी: संसाधनों का लाभ

अजित पवार एनसीपी का प्रदर्शन:

- कुल सीटें जीतीं:1,124 (सभी निकायों में)
- जीत प्रतिशत: 53.8%
- पुणे महानगरपालिका: 20 सीटें
- पिंपरी-चिंचवड़: 28 सीटें (बहुमत)

सत्ता में होने का लाभ और संसाधनों की उपलब्धता ने अजित पवार गुट को बढ़त दिलाई।

क्रमशः

आशीष चंद्रनारायण दुबे
राजनीतिक रणनीतिकार एवं चुनाव विश्लेषक
द पॉलिटिकल लैब

बसंत पंचमी के बाद आ सकती निगम-मंडलों की सूची

सीएम दावोस के अपने दौरे से लौटकर तकरीबन फाइनल हो चुकी सूची पर आखिरी दौर का करेंगे मंथन

इंदौर। अपनी ही पार्टी के सत्ता में होने के बावजूद सरकार से किनारे बैठे पूर्व मंत्री विधायक और पूर्व विधायकों का एक साल का सब्र जब टूटने को है। तब ये आस बंधने लगी है कि बसंत पंचमी बीतने के साथ सूने पड़े प्रदेश के निगम मंडलों में बहार आ जाए। जानकारी के मुताबिक तकरीबन फाइनल हो चुकी निगम मंडल और प्राधिकरण की सूची के जारी होने की अंतिम संभावित तारीख आ गई है। निगम मंडल के लिए प्रतीक्षारत नेताओं को बीजेपी में बसंत में बहार की सौगात दे सकती है।

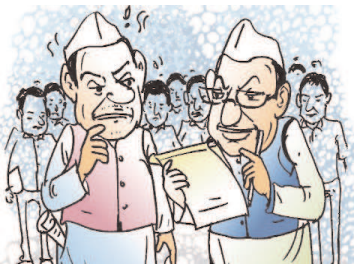

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐन बाद पूरी पार्टी लोकसभा चुनाव में जुट गई थी। लोकसभा चुनाव के छह महीने बीत जाने के बाद भी करीब डेढ़ साल का समय गुजर चुका है। जो मंत्री पद की कतार में थे वो पूर्व मंत्री बनकर बाट जोह रहे हैं कि उनके भी दिन बहुरेंगे। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों में शुमार गोपाल भार्गव निगम मंडलों में नियुक्ति से जुड़े सवाल पर पहले ही कह चुके हैं कि हमारे भी दिन आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि कब? पहले बताया गया कि सूची लगभग फाइनल है और मकर संक्राति के बाद ऐलान हो जाएगा, लेकिन अब नई तारीख बताई जा रही है। नई तारीख बसंत पंचमी के बाद की है।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव स्विट्जरलैंड के दावोस के अपने दौरे से 23 जनवरी तक लौटेंगे। माना जा रहा है कि बसंत पंचमी के बाद तकरीबन फाइनल हो चुकी सूची पर आखिरी दौर का मंथन करेंगे। उसके बाद ये सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि लगभग 30 से ज्यादा नेताओं के नाम फाइनल हो चुके हैं।

योग्यता ही एक मात्र पैमाना

मध्य प्रदेश में निगम मंडल में वरीयता किसे होगी, क्या पैमाना होगा? मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और संगठन का एकाधिकार होने के बावजूद क्राइटेरिया क्या होगा? किस आधार पर नेताओं के पद के लिए चुनाव होंगे। ये देखने वाली बात होगी।

वजह ये है कि इस बार हर निगम मंडल और प्राधिकरण के लिए एक अनार, सौ बीमार जैसे हालात हैं। केवल बीजेपी के ही नहीं कांग्रेस से आए वे नेता भी इस कतार में हैं जिन्हें इस भरोसे से ही पार्टी में लाया गया था कि वे नवाजे जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव कहते हैं, बीजेपी एक संगठन आधारित दल है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में भी योग्यता और क्षमता के हिसाब से अवसर दिया गया। और अब जब निगम मंडलों में नियुक्ति होनी है तब भी योग्यता और क्षमता के मुताबिक ही मौके दिए जाएंगे।

ये पूरी तरह मुख्यममंत्री डॉ. मोहन यादव और संगठन के अधिकार क्षेत्र की बात है कि वे किसे अवसर देते हैं।

प्रदेश में 46 खाली निगम मंडल

मध्य प्रदेश में इस समय 46 निगम मंडल हैं। इसके अलावा प्रमुख शहरों में बने प्राधिकरण में भी नियुक्ति होनी है। इन पदों के लिए प्रदेश के दिग्गज पूर्व मंत्रियों के नाम सबसे आगे हैं।

जिनमें सीनियर मोस्ट नेता जयंत मलैया, गोपाल भार्गव के साथ अरविंद भदौरिया, ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह और अर्चना चिटणीस के नाम शामिल हैं। जानकार बताते हैं कि मंत्री पद से छूटे जितने नेता हैं जिनका सत्ता में सीधे तौर पर समावेश नहीं हो पाया है, उनकी आखिरी उम्मीद निगम मंडल ही बचते हैं।

लिहाजा नेताओं में छटपटाहट स्वाभाविक ही है। कई काफी वरिष्ठ नेता अभी खाली बैठे हैं। कई कम अंतर से चुनाव हारे पूर्व मंत्री भी हैं। और पार्टी के सामने चुनौती व्यक्ति के साथ क्षेत्र की भी है।

2026 की शुरुआत हो चुकी है। दो साल बाद फिर विधानसभा चुनाव हैं और उसकी पृष्ठभूमि का अहम पड़ाव ये नियुक्तियां भी होंगी।

कांग्रेस की वाटर लैब पानी की जांच के लिए वार्ड-वार्ड घूम सच्चाई सामने लाएंगी

इन्दौर। भागीरथपुरा में इन्दौर नगर निगम द्वारा सप्लाई पानी से हुई मौतों के मामले में लगातार सक्रिय कांग्रेस सत्ता पक्ष पर हमलावर होते हुए धरना प्रदर्शन के साथ जांच कार्रवाई की मांग करते घटना के बारे में उनके उपर सच छुपाने का आरोप लगा छिपाए जा रहे सच को उजागर करने का प्रयास कर रही है। इसके चलते शहर कांग्रेस ने विगत दिनों बड़ा गणपति से अहिल्या प्रतिमा तक न्याय यात्रा निकाली थी वहीं कई राज्य तथा केन्द्र स्तरीय नेताओं के वहां पहुंचने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी भागीरथपुरा पहुंचे थे। और पीड़ितों को न्याय दिलाने के साथ जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर घटना का सच उजागर करने के लिए न्यायिक जांच की मांग की थी।

मामले में अब शहर कांग्रेस अपनी वाटर लैब शहर में घुमाएगी। जो पानी की जांच कर शहर में सप्लाई हो रहे दूषित पानी की सच्चाई सामने लाएंगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे के अनुसार इतनी मौतें होने के बाद भी जिम्मेदारों द्वारा सबक नहीं लिया जा रहा है। शहर में कई जगह अभी भी गंदा पानी आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाते चेतावनी दी कि सरकार दूसरे भागीरथपुरा का इंतजार कर रही है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। शहर में आ रहे गंदे पानी की जांच कांग्रेस निःशुल्क करेगी। कांग्रेस की चलित वाटर लैब शहर के 85 वार्डों में घूमेगी और पानी की जांच करेगी। इससे नगर निगम द्वारा लोगों को दिए जा रहे गंदे पानी की पोल भी खुलेगी।

विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस ने किया अनुठा विरोध प्रदर्शन

- कार्यकर्ता को शाह का मुखौठा पहनाकर हथकड़ी लगाई
- गिरफ्तार कर निकाला जुलूस, फिर पुलिस के पास लेकर पहुचें

इंदौर। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह की मुश्किलें और बढ़ गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर सड़क पर आकर विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कॉंग्रेस कार्यकर्ताओ ने राजधानी भोपाल में अनूठा प्रदर्शन किया। यहॉं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमित शर्मा के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता को मंत्री विजय शाह का मुखौटा पहनाकर उसे हथकड़ी लगाकर पीसीसी के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता पीसीसी से मंत्री का मुखौटा पहने हुए अपने कार्यकर्ता को किसी गिरफ्तार किये गये आरोपी की तरह हथकड़ी पहनाए हुए उसका जुलूस निकालते हुए पांच नंबर स्टॉप पर स्थित पुलिस चौकी पहुंचे। यहां मंत्री का मुखौटा पहने व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमित शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा की मंत्री विजय शाह ने देश की बेटी सोफिया कुरैशी का अपमान किया। सोफिया ने देश का मान-सम्मान बढ़ाया और उसे अपमानित करने वाले मंत्री को मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बचाने में लगी हुई है।

छह महीनों से सरकार लगातार मंत्री को संरक्षण दे रही है। शर्मा ने आगे कहा की मध्य प्रदेश की सरकार जिस मंत्री का संरक्षण कर रही थी, उसपर मुकदमा चलाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सत्य की जीत हुई है मोहन सरकार की हार हुई है। कार्यकर्ता को विजय शाह का मुखौटा लगाकर हथकड़ी पहनाकर जुलूस निकालने की बात पर अमित शर्मा ने कहा की हम मंत्री विजय शाह के घर गए थे, वे घर से फरार हैं। हमें विजय शाह केरवा के जंगल में घूमते हुए मिले हमने उन्हें प्रतीकात्मक रूप से गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया है।साथ ही कांग्रेस नेताओ ने चेतावनी दी है कि यदि विजय शाह को मंत्री पद से नहीं हटाया जाता है, तो कॉंग्रेसं सीएम मोहन यादव का घर घेरेंगे।

एक लाख लाड़ली बहनें घट गईं सालभर में... नए पंजीयन फिलहाल बंद

हर माह 21 करोड़ रुपए से अधिक की होगी बचत, नई लाड़ली बहनें भी पात्रता की है कतार में

इंदौर। पिछला विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जो लाडली बहना योजना शुरू की गई उसने सरकार तो बनवा दी, मगर हर महीने अब 1836 करोड़ रुपए की राशि खातों में जमा कराना पड़ती है, जिसके चलते शासन की वित्तीय स्थिति खस्ता है और लगातार लोन लेना पड़ रहा है। अब 1200 की बजाय 1500 रुपए की राशि लाडली बहनों को दी जा रही है।

हालांकि पिछले एक साल में एक लाख लाडली बहनें घट भी गई और नई लाडली बहनें नहीं जुड़ सकी, क्योंकि इसका पंजीयन ही फिलहाल बंद है। मध्यप्रदेश की तरह अन्य राज्यों ने भी इसी तरह की योजनाएं चुनाव जीतने के लिए शुरू कर दी। अभी बिहार चुनाव में ही 10-10 हजार रुपए की राशि एकमुश्त महिलाओं के खातों में जमा कराई गई और वहां भी सरकार बनाने में यह योजना लाभदायक साबित हुई। मध्यप्रदेश में भी जून-2023 से यह योजना शुरू की गई और हजार रुपए की किश्त लाडली बहनों के खातों में जमा होना शुरू हुई। उसके बाद मोहन सरकार ने योजना की राशि 1250 रुपए की और उसके बाद फिर अभी दीपावली से 1500 रुपए कर दिए गए। यह योजना जब शुरू हुई तब 1 करोड़ 31 लाख लाडली बहनों के खातों में राशि जमा हो रही थी, जो अब 1 करोड़ 26 लाख हो गई है। यानी 5 लाख लाडली बहना घट गई और अभी एक साल में ही एक लाख लाडली बहनें कम होने से हर माह 21 करोड़ रुपए की राशि शासन की बचने लगी। दूसरी तरफ नए पंजीयन इस योजना में अभी तक शुरू नहीं किए जा रहे हैं और लाखों बहनें लाडली होने की कतार में खड़ी हैं। दरअसल, मृत होने वाली बहनों के साथ-साथ 60 साल से अधिक उम्र की बहनों के नाम सूची से कट जाते हैं। अभी पंजीयन इसलिए भी शुरू नहीं किया जा रहा है क्योंकि संख्या बढ़ने पर हर माह खजाने पर और वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। अभी जनवरी तक ही 32वीं किश्त के रूप में अभी तक इस योजना के तहत 50 हजार करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।

1836 करोड़ रुपए की राशि अभी 16 जनवरी को खातों में ट्रांसफर की है और 1 करोड़ 25 लाख लाडली बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। दूसरी तरफ इस योजना के तहत धीरे-धीरे राशि भी बढ़ाई जाना है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि रोजगार परख उद्योग में काम करने पर बहनों को 5 हजार रुपए तक की मदद भी की जाएगी।